



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]
No. 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 2004/चैत्र 13, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 2004/CHAITRA 13, 1926

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2004

का.आ. 451(अ).—अन्तर्राष्ट्रिय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों से अन्तर्राष्ट्रिय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 3 के अधीन अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अन्तर्राष्ट्रिय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों का बातचीत के द्वारा तय नहीं किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्तर्राष्ट्रिय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित "कृष्णा जल विवाद अधिकरण" नामक एक जल विवाद अधिकरण का गठन करती है जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(i) न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार न्यायधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय	—	अध्यक्ष
(ii) न्यायमूर्ति श्री एस.पी. श्रीवास्तव न्यायधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय	—	सदस्य
(iii) न्यायमूर्ति श्री डी. के. सेठ न्यायधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय	—	सदस्य

[फा. सं. 5/7/2002-बी एम]

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार तथा उनके नाम से,

वी. के. दुग्गल, सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2004

S.O. 451(E).— Whereas requests have been received under Section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), from the Governments of Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh to refer the water disputes regarding the inter-State river Krishna, and the river valley thereof, to a Tribunal for adjudication;

And whereas the Central Government is of opinion that the water disputes regarding the inter-State river Krishna, and the river valley thereof, cannot be settled by negotiations;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 4 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Water Disputes Tribunal called 'the Krishna Water Disputes Tribunal', with headquarters at New Delhi, for the adjudication of the water disputes regarding the inter-State river Krishna, and the river valley thereof, consisting of the following Members nominated in this behalf by the Chief Justice of India, namely :—

(i)	Shri Justice Brijesh Kumar Judge of the Supreme Court of India	—	Chairman
(ii)	Shri Justice S.P. Srivastava Judge of the High Court of Allahabad	—	Member
(iii)	Shri Justice D.K. Seth Judge of High Court of Calcutta	—	Member

[F. No. 5/7/2002-BM]

By Order and in the Name of The President of India,

V. K. DUGGAL, Secy.